जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

हिण्डौन सिटी

Rashtradoot

फोनः- 230200, 230400 फैक्सः- 07469-230600 वर्षः 14 संख्याः 289 प्रभात हिण्डौन सिटी, शनिवार 20 अगस्त, 2022 पो. रजि.SWM-RJ-6069/2017-18 पृष्ठ 8 मूल्य 2.00 रु.

जॉर्जिया में इस बार लॉगरहैड सी टर्टल नैस्टिंग का नया रिकॉर्ड बना है। इस वर्ष तीन अगस्त को यहां टर्टल नैस्ट की गिनती 3,960 पहुंच गई जो कि 33 साल में, अर्थात् 1989 से सर्वे शुरु होने के बाद से, सर्वाधिक थी। वर्ष 2004 में सबसे कम 358 नैस्ट देखे गए थे, उसे देखते हुए नैस्ट की संख्या दस गुना बढ़ गई है। जॉर्जिया सी टर्टल प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर मार्क डॉड, जो वरिष्ठ वन्यजीव वैज्ञानिक हैं, ने कहा कि लॉगरहैड टर्टल लम्बा जीते हैं और 35 साल की उम्र के बाद प्रजनन कर पाते हैं। जॉर्जिया की लॉगरहैड टर्टल की आबादी को अमेरिका में "खतरे में" माना गया है। हालांकि इनकी आबादी 1990 के बाद से प्रति वर्ष चार प्रतिशत बढ़ी है, पर लक्ष्य हासिल करने में 20 साल और लगेंगे। लगभग 300 पाउण्ड वजनी मादा लॉगरहैड मई से अगस्त के बीच प्रजनन के लिए तट पर आती है और जमीन में गड्ढा करके प्रायः रात में अंडे देती है। यहां जितने भी सी टर्टल घर बनाते हैं, सभी की सुरक्षा और निगरानी जॉर्जिया सी टर्टल कोऑपरेटिव नामक संस्था करती है। संस्था लगभग तीस साल से नैस्टिंग सीज़न के दौरान क्षेत्र की निगरानी कर रही है।

"गैर स्थानीय" निवासियों को मतदान का अधिकार मिलेगा कश्मीर में

इस नयी व्यवस्था से 23 लाख नये वोटर जुड़ेंगे कश्मीर के टोटल 76 लाख मतदाता की सूची में

-श्रीमंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 अगस्त। बिहार की राजनीतिक सत्ता के हाथ से जाने और बढ़ती मंहगाई व बेरोजगारी के मुद्दो पर नरेन्द्र मोदी सरकार के प्रदर्शन को लेकर आम जनता की असहजता से निराश भाजपा गुजरात के आगामी विधानसभा चुनावों में एक बार फिर कश्मीर मुद्दे का बढ़ा-चढ़ा कर प्रचार कर सकती है। गुजरात के बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं।

जम्मू और कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी हदेश कुमार ने बुधवार को घोषणा की कि अगले वर्ष होने जा रहे विधानसभा चुनावों में राज्य से बाहर के लोगों को भी वोट देने की अनुमति दी जाएगी। इसका मतलब है कि 3 लाख अतिरिक्त वोटर्स का जुड़ना या क्षेत्र के मतदाताओं की सूची में 30 प्रतिशत वोटर्स बढ़ जाना। इस सूची में वर्तमान में 76 लाख वोटर्स हैं। नए वोटर्स में सैन्य कर्मी, प्रवासी मजदूर और प्राइवेट सैक्टर के कर्मचारी होंगे। यह कदम भाजना के "एक देश-एक संविधान" सिद्धान्त पर फिट बैठता है क्योंकि अपने गृह राज्य के बजाए अन्य राज्यों में रह रहे भारतीय नागरिक कुछ निश्चित मापदण्डों को पूरा करते हैं तो उन्हें वोट देने की अनुमति है। कश्मीर जो कि भारत का एकमात्र मुस्लिम बाहुल्य राज्य है और जिसने पिछले तीन दशकों में बगावत फेली है, में इसको लेकर चिन्ताएं बढ़ गई हैं, कि केन्द्र सरकार यहां बड़े प्रभावी जनसांख्यिकीय परिवर्तन करना चाहती है। अगस्त 2019 से जब धारा 370 समाप्त की गई, भारत सरकार ने नए आवास कानून सहित कई विधायी कदम उठाए हैं, इनके तहत क्षेत्र में 15 वर्षो से अधिक समय तक निवासरत प्रत्येक भारतीय को नागरिकता का अधिकार प्रदान किया गया है। गैर कश्मीरीयों को भी घाटी में जमीन खरीदने के अधिकार दिए गए हैं।

- **सेना के जवान व अफसर, माइग्रैंट लेबर तथा प्राइवेट सैक्टर व पब्लिक सैक्टर के कर्मचारी अब कश्मीर में मतदान के अधिकारी होंगे, अगर वे पन्द्रह साल से ज्यादा समय से कश्मीर में रह रहे हैं। इन लोगों को कश्मीर में सम्पत्ति खरीदने का अधिकार भी मिलेगा।**
- **यह नयी व्यवस्था, जिसकी घोषणा कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी हृदेश कुमार ने बुधवार को की थी, भाजपा के "एक देश, एक संविधान" सिद्धांत पर आधारित है।**
- **अतः अगर इस व्यवस्था का भाजपा को कश्मीर के चुनाव में ज्यादा लाभ मिले ना मिले, पर देश में गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, व छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनावों में जरूर लाभ मिलेगा।**
- **महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला आदि, कश्मीर के नेताओं ने इसे, "बाहरी वोटर" लाकर कश्मीर में चुनाव जीतने की मोदी सरकार की साजिश बताया।**

मोदी सरकार ने पूर्व में राज्य के एक नये चुनावी मानचित्र की घोषणा की थी, जिसमें हिन्दू बाहुल्य जम्मू क्षेत्र में विधानसभा सीटों की संख्या 37 से बढ़ाकर 43 कर दी गई थी। यद्यपि कश्मीर घाटी में एक ही निर्वाचन क्षेत्र

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'प्रॉफैशनल जीवन में पिछड़ने से रोकने के लिये अंग्रेजी माध्यम के स्कूल व कॉलेज खोलेंगे'

हिन्दी भाषी छत्तीसगढ़ ने भी बच्चों व युवाओं को अंग्रेजी में पारंगत करने की स्कीम बनायी

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 अगस्त। हिन्दी बैल्ट के राज्य छत्तीसगढ़ ने निर्णय लिया है कि उसे अपने युवाओं को व्यवसाय एवं रोज़गार बाजार की प्रतिस्पर्द्धा में खड़ा करने के लिये अंग्रेजी की जरूरत है।

यही कारण है कि छत्तीसगढ़ सरकार अगले शैक्षणिक सत्र, 2023 से अंग्रेजी माध्यम के 10 कॉलेज खोलेगी। राज्य में अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय तो पहले से ही बड़ी संख्या में संचालित हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्विटर पर अपने इस निर्णय की घोषणा करते हुये कहा कि सरकार के इस निर्णय का उद्देश्य अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा को और बढ़ावा देना है।

कई राज्यों ने उनकी सरकारों द्वारा संचालित चयनित स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षण के माध्यम के रूप अंग्रेजी का चयन कर लिया है क्योंकि अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करना आज युवाओं की आम आकांक्षा बन चुका है।

- **यह स्कीम नरेन्द्र मोदी ने चालू की थी, जब वे गुजरात के मु.मंत्री थे तथा अब इस सोच को अपनाने वालों में उत्तर प्रदेश, आंध्र, आदि हैं।**
- **पर, सभी जगह वो ही दिक्कत सामने आ रही है, जो राजस्थान में आई है, इन नये स्कूल कॉलेजों के लिये अध्यापक कहां से लायें।**
- **कई राज्यों में, उदाहरण के लिये छत्तीसगढ़ के 44,000 सरकारी स्कूलों में काफी स्कूलों में से अभी बेसिक सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं, नये टीचर्स की नियुक्ति तो दूर की बात है।**

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, ने इस आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाते हुये, कुछ सरकारी विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम शुरु कर दिया था क्योंकि वे चाहते थे कि राज्य के बच्चे प्रतियोगिता के क्षेत्र में पीछे न रहें। इसी प्रकार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने भी कई साल पहले अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोल दिय हैं।

अभी-अभी आंध्र प्रदेश ने भी अपने स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का रूप दे दिया है तथा राज्य सरकार चाहती है कि आगामी कुछ ही वर्षों में राज्य के सभी विद्यालय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बन जायें। राज्य के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने इस प्रोजैक्ट में निजी रुचि ली है तथा राज्य सरकार का एकमात्र उद्देश्य विद्यार्थियों को 21वीं सदी की चुनौतियों तथा कैरियर निर्माण के अवसरों के लिए पूरी तरह तैयार करना तथा उन्हें वैश्विक नागरिक के रूप में विकसित होने में समर्थ बनाना है। अंग्रेजी माध्यम शिक्षा की माँग समाज के सभी वर्गों, खासतौर से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की ओर से आती रही है। श्री वास्तव ने कहा कि लेकिन सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती होगी- विभिन्न विषयों को अंग्रेजी भाषा में पढ़ाने में सक्षम शिक्षकों और व्याख्याताओं की तलाश। उन्होंने आशंका व्यक्त की कि विभिन्न सरकारी कॉलेजों के मौजूदा शिक्षकों के पास इस कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम देने लायक अंग्रेजी भाषा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता।

राज्य सरकार ने अभी-अभी हाल ही में 1300 असिस्टैंट प्रोफेसर रखे हैं जिनमें से बहुत से लोग अंग्रेजी माध्यम

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

रिज़र्व बैंक की चेतावनी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 अगस्त। कांग्रेस महासचिव तथा मुख्य प्रवक्ता जयराम रमेश ने शुक्रवार को सरकार से कहा कि वह आर.बी.आई. के मासिक बुलेटिन में दी गई इस चेतावनी पर ध्यान दे कि "पी.एस.बी. (पब्लिक सैक्टर बैंक) के बड़े पैमाने पर निजीकरण से देश का भला होने की बजाय, बुरा ज्यादा होगा।

रमेश ने एक ट्वीट में कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की संख्या 27 से 12 तो पहले ही हो चुकी है और सरकार की योजना है कि इन्हें कम कर के, इसकी संख्या एक कर दी जाये। उन्होंने कहा कि आर.बी.आई. ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसा करना सर्वनाश

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सी.बी.आई. ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री सिसोदिया के निवास पर छापा मारा

सिसोदिया, जो आबकारी मंत्री भी हैं, पर आरोप है कि, उन्होंने नयी आबकारी नीति के तहत शराब की दुकान प्राइवेट पार्टियों को देने की मुहिम चालू कर, भारी रकम प्राप्त की

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 अगस्त। सैंट्रल ब्यूरो ऑफ इनवैस्टिगेशन (सी.बी.आई.) ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के उपमुख्यमंत्री के आवास पर आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के आरोपों पर रेड डाली। आरोप है कि गत नवम्बर में शुरू हुई इस नीति में प्राइवेट कम्पनियों को शराब के लाइसैंस देने में भारी घोटाला किया गया है।

एक एफ.आई.आर. दर्ज करते हुए सी.बी.आई. ने राष्ट्रीय राजधानी में 20 से ज्यादा स्थानों पर रेड की, सिसोदिया ने ट्वीट किया कि, "सी.बी.आई. मेरे घर पर है। मैं जांच एजेंसी के साथ को ऑपरेट करूंगा। उन्हें मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिलेगा।"

एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा, सी.बी.आई. आ गई है। हम ईमानदार हैं लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में जो भी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'मछलियों का कोविड टैस्ट करो संक्रमण रोकने के लिये'

चीन हास्यास्पद कदम उठा रहा है, कोविड के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिये

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 अगस्त। कहा जाता है कि कोविड के प्रसार को लेकर इतना ज्यादा चिन्तित एवं हताश हो चुका है कि उसने मछुआरों के साथ ही, उनके द्वारा पकड़ी जाने वाली मछलियों की भी कोविड जाँच शुरु कर दी है। चीन के इस कदम का खूब मखौल उड़ाया जा रहा है तथा सोशल मीडिया पर इससे संबंधित चुटकूलों की बाढ़ आ रही है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के कुछ टिप्पणीकारों ने सुझाव दिया है कि चीन जीवित मछलियों की कोविड जाँच कर रहा है ताकि मछुआरों मछलियों को समुद्रों में ही बने रहने दें। मछलियों का महासागर में उनके लिये एक प्रकार का क्वारंटीन ही है।

लेकिन चीन की कोविड-नियंत्रण व्यवस्था एक प्रकार से मजाक बनकर रह गई है। कोविड-नियंत्रण एक बहुत बड़ा राजनैतिक मुद्दा बन गया है क्योंकि देश के शीर्ष नेता शी जिनपिंग ने सुस्थापित राजनैतिक परम्परा को उलट दिया है, जिसके अन्तर्गत, सर्वोच्च पद पर बैठे नेता के कार्यकालों की भी प्रतिबंधों द्वारा नियंत्रित होती थी।

शी राजनैतिक व्यवस्था तथा सामान्यजनों के सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं पर भी अपनी पकड़ बढ़ा दी है क्योंकि जल्दी ही कम्प्यूनिस्ट पार्टी का अधिवेशन होना है, जिसमें शी को जीवनभर राष्ट्रपति बने रहने के लिये उनके कार्यकाल-विस्तार का समर्थन होना है। इसके लिये सभी मोर्चों पर शान्ति होना जरूरी है।

लेकिन विडम्बना यह है कि सभी मोर्चों पर चीन की स्थिति खराब है। चीन की अर्थव्यवस्था जबरदस्त रूप से पतोन्मुखी होती जा रही है। जनता में प्रॉपर्टी कंपनियों को लेकर बड़े पैमाने पर नाराज़गी है क्योंकि वे उन खरीदारों को भी घर नहीं दे पा रही हैं, जो कर्ज लेकर मकानों की कीमत का भुगतान उन्हें पहले ही कर चुके हैं।

और सबसे बुरी स्थिति कोविड ने कर रखी है जो जंगल की आग की तरह फैलता ही जा रहा है, जबकि पूरे देश में आवागमन पर जबरदस्त प्रतिबंध लगे हुये हैं तथा "नो-कोविड" नीति पूरी सख्ती के साथ अमल में लाई जा रही है जिसकी देख-रेख तथा नेतृत्व स्वयं शी जिनपिंग व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं। लेकिन तथ्य यह है कि इसे सीमित एवं समाप्त करने के तमाम सरकारी प्रयासों

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)